श्री गोविन्दराम मिरी (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री जयपाल रेड्डी जो तथ्य प्रकाश में लाए हैं और जो मांग उन्होंने की है, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए इतना कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने वर्मा कमीशन की जो रिकमन्डेशन्स हैं, पिक एंड चूज का मेथड न अपना करके ऐज ए होल उनको लें और जिनके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है, उन पर भी कार्रवाई हो क्योंकि "मीठा-मीठा मेरा और कड़वा-कड़वा तेरा" ऐसा सिद्धांत नहीं होना चाहिए । ज्वाइंट रिस्पान्सिबिलिटी होती है, इसलिए अधिकारियों की आड़ में अपनी कमजोरी छिपाने का बहाना वर्तमान सरकार न ढूंढे और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, किसी ने कहा है :—

"उन्हीं का शहर, वही मुद्दई, वही मुनसिफ, मैं जानता हूं कुसूर मेरा ही निकलेगा" इसलिए मैं मांग करता हूं कि जयपाल रेड्डी जी ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, मैं अपने आपको उससे सम्बद्ध करते हुए मांग करता हूं कि अधिकारियों को ऐस्केप गोट बनाकर जो कार्रवाई की जा रही है, वह अनुचित है। उनके खिलाफ कार्रवाई बंद की जानी चाहिए । यह मैलाफाइडि इंटेंशन से किया जा रहा है आपसी झगड़े को उजागर करने के लिए। धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PAOIOURI): This matter is over. Now I adjourn., *(Interruptions).,*

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir, what about the statement of Mr. P. Chidambaram) which he was supposed to give to the House? Sir, please direct the Government to give that state. ment by tomorrow.. *(Interruptions)...*

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : ये जीरो आवर कब लिए जाएंगे ?

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, let there be lunch hour.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRT SURESH PACHOURI): I adjourn the House for lunch till 2.40 P.M.

The House than adjourned for lunch at thirty-niM minutes past one of the clock.

The House reasscmWed after lunch at forty -four minutes past two of the clock,

The Vice-Chairman (Shri Suresh Paelioiiri) in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Now we Will continue with the Zero Hour submmions. Shri Janardan Yadav. Not present. *Shri* Sunder Singh Bhandarj.

RE: HIKE IN PRICES OF FERTILI-ZERS

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । ऐसा रिपोर्ट हुआ है कि कृषि मंत्रालय ने उत्पादकों की फास्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर अनुदान बढ़ाने की मांग को नामंजूर किया है । उसके लिए उनके पास क्या कारण है, यह उसमें नहीं दिया गया है । इसका नतीजा यह होगा कि दोनों उर्वरकों की कीमत में बढ़ोत्तरी हो जाएगी । इस बात की आशंका है कि डी.ए.पी. का भाव, जो 8500 के लगभग चल रहा है, वह 9300 रु० या 9400 तक बढ़ जाएगा । इस समय यूरिया का बिक्री मूल्य 3320 रुपए है । दोनों के दामों में तीन गुना अंतर है और इसमें पी.ओ.पी. का जो अनुपात है, उसमें असंतुलन पैदा होने की आशंका है । 1992–93 में पी.ओ.के. का अनुपात 9.3:3.61 रह गया था । 1993–94 में डी.ए.पी. की खपत 34 लाख 80 हजार टन थी, अप्रैल 94 से फरवरी 95 तक यह 31 लाख टन दर्ज की गयी है। यद्यपि कृषि मंत्रालय कहता है कि यह खपत 36 लाख 86 हजार टन है । मैं समझता हूं कि कृषि मंत्रालय को फिर से इस फिगर को चेकअप करना चाहिए और सही स्थिति को समझने का प्रयत्न करना चाहिए । 1995–96 में फास्फेटिक एसिड

और अमोनिया की कीमत 38 व 30 प्रति टन के हिसाब से बढ़ जाएगी । इससे उत्पादन लागत में वृद्धि होगी । घरेलू डी.ए.पी. की उत्पादन लागत में इससे 800 रुपये टन की वृद्धि की जाएगी । किसानों को भी इसके लिए अधिक दाम देना पड़ेगा । 1994-95 की दूसरी छमाही में डी.ए.पी. का बिक्री मूल्य 8500 रूपया प्रति टन था तो इसकी खपत बढ़ गयी थी । पर अब जब यह मूल्य 9300 या 9400 हो जाएगा तो डी.ए.पी. की खपत पर अधिक प्रतिकूल असर होगा।

अतः मेरी सरकार से मांग है कि फास्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों पर अनुदान बढ़ाने के विषय पर पुनर्विचार किया जाए । इस समय केवल एक हजार रुपया प्रति टन के हिसाब से अनुदान दिया जाता है, जो कि अपर्याप्त है । अगर कीमतों में संतुलन न हुआ तो इसका सीधा असर भूमि की उर्वरक शक्ति पर पड़ेगा और इससे उपज की दीर्घकाल में घटने की आशंका है । इसलिए मैं आपकी मार्फत सरकार से इस नीति पर पुनर्विचार करने की मांग करता हूं । धन्यवाद ।

Re. OVERCAPITALISATION AND HIGH COST OF POWER BY ENRON AND COUNTER GUARANTEE BV GOVERNMENT

SKRI N. GIRI PRASAD (Andhra Pradesh); Mr. Vice-Chirman , hank you very-much. I am raising an issue with regard to the overcapitalisation of the Enron project, Dabhol Power Company. A lot Of controversy is going on in this regard. The Maharashtra Government also has instituted an inquiry. But the report has not come out so far. The situation is very precarious. Many pec- . ple have gathered at the site and are holding agitation for cancelling the project. On| the other hand. the Central Gvernment , particularly the Power Minister, is making contradictory state. ments Mr. Salve, when he was in Hyderabad, said' that those who are criticising this project are anti-national. The entire Press, public opinion and many Members of Parliament are against it. They have criticised it because there is over-capitalisation Consequently, the power project agreement entered into between the Maharashtra Government and Enron stipulates that the Maharash tra Electricity Board will buy power ranging from Rs. 2.40 to Rs. 4 per unit. This is in excess 50 per cent to 100 per-cent over what is sold by other com panies. Moverover, in the US, it is stated that the power generated by the gas-based power plaats is sold at three to four cents. But, here in our country it is being sold at seven to eight cents. This type of over-capitalisation and high cost of power which is being charged by tha Enron Company is not only creating trouble for the people, but it is also adversely affecting our indnstrialisation process and price stability in the country. There are some seven fast track companies any city this company has enteied into purehase agree-*ritent.* The other fast track compan ies' thy also end, to such signilar agreements. If we agreed to the stipulations in the case, thempony, naturally, the other comparces will also demand\the same price ____so, this will escalate into a major nation trisis . Uni fortunately, the Governmes . fes also given a counter guarantee to this . upany and it plans to give such counter guaraA' tee to the other fast track, companies also. I have read that the Government has changed its policy to some extent in the case of future projects. But as far as these seven projects are concerned, it wants to stick to this policy. Unfortunately, our Foreign Minister when he went 10 the US, assured, the Congres-sionsil leaders that the Chief Minister ot Maharashtra would also come there and assure them about the continuance of these projects or something like that. So. if these types of projects are taken up. naturally, our country will face bigger problems. Morever. even the World Bank President criticised it because there was no transparency and there was no bidding, If you enter into such behind-